London for negotiations? He has not replied to that.

THE VICE- CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : All right . The hon. Members made their points. Many Members spoke on this. The matter was raised the day before yesturday also. And today again it was raised by Mr. Mathur. The Government has already clarified its position, and they have expressed their stand. The hon. Prime Minister is also coming to this House to reply to the discussion on the Ministry of Defence. So, I think, it does not require a separate sta'ement. (*Interruptions*) I think that is not needed.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Kindly do not give a ruling like this. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) On this matter, a separate statement is not necessary.

SHRI SIKANDAR BAKHT : Let the Government decide about it. For God's sake, do not give a ruling. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Now, we go to the Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Drinking Water Problem in Gujarat

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, गुजरात में खास कर के कच्छ और सौराष्ट्र में जो सूखा पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुजरात में जो सूखे से उत्पन्न हालत है, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। गुजरात राज्य में खास कर के कच्छ और सौराष्ट्र में भंयकर सूखा पड़ा हुआ है। इस विकट सूखे की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार फौरन उपाय करे और वहां के पशु-धन को बचाने की कोशिश करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात राज्य की 182 तहसीलों में से मात्र 25 से 30 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सरकारी कायदा-कानून के मुताबिक जहां बरसात एक चौथाई से कम हुई हो, उसकी पूरी सूचना अक्तूबर तक सरकार के पास आ जाती है। हाल ही में सौराष्ट्र-कच्छ के तमाम जिलों के कलेक्टरों ने गुजरात सरकार के पास अपने-अपने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है किन्तु सरकार ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण मात्र 25 से 30 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कैटल कैम्पस, राहत कार्यों, पीने के पीने का पानी, चारा आदि की सुविधाएं लोगों और पशुओं को देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। सौराष्ट्र और कच्छ में हजारों पशु चारा और पानी के अभाव में खत्म हो गए हैं और लोगों ने अपनी तथा अपने पशुओं की रक्षा के लिए पशुओं के साथ पलायन प्रारम्भ कर दिया है। हाल ही में गुजरात सरकार प्रति पशु चार रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है लेकिन यह बहुत ही कम है। इसे बढ़ा कर 8 रुपए करना चाहिए, यह मेरी मांग है। कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं गुजरात के लोगों और पशुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहती हैं लेकिन गुजरात सरकार की ओर से इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसमें कुछ क्षेत्रीय संस्थाओं की जरा भी मदद नहीं की गई। पानी की इतनी गंभीर परिस्थिति है, गांवों की बहू-बेटियों को पीने का पानी लाने के लिए तीन-चार किलोमिटर दूर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं के लिए पीने के पानी का प्रबंध कैसे किया जाए ? हाल ही में गांवों में पीने के पानी टैंकरों से उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन वह भी प्रति व्यक्ति 15 लीटर दिया जा रहा है जो बहुत ही कम है। सरकारी एजेन्सियों के जरिए कन्ट्रेक्ट द्वारा जो चारा पहुंचाया जा रहा है, वह सड़ा हुआ और कम वजन में दिया जा रहा है। इस प्रकार की धांधलियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ लोगों के समिति बना कर के पर्यवेक्षक के रूप में भेजनी चाहिए। गुजरात इस देश का एक गौरवशाली प्रदेश है। सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सरकार ने 85 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है। किन्तु अभी तक उसमें से मात्र 35 करोड़ ही राज्य सरकार को भेजा गया है। अतः माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया से मेरा निवेदन है कि इस भयानक सूखे की स्थिति

का जायजा ले कर गुजरात के सभी जिलों का जायजा लेने के बाद तत्काल भारत सरकार की ओर से एक समिति वहा भेजी जाए जो सभी जिलों का दौरा करें और केन्द्रीय सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए सिफारिश करें ।

ताकि वहां के लोगों और पशुओं के जीवन की रक्षा हो सके । साथ ही यह भी मैं मांग कर रहा हूं कि जो धनराशि अभी तक सूखा क्षेत्रों के लिए इक्विप की गयी है और अभी तक वहां भेजी नहीं गयी है, उसे तुरन्त भेजने की व्यवस्था की जाए ताकि वह समय से लोगों को मिल सके और उनकी परेशानियां समाप्त हो सके ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे एसोसिएट कर रहा हूं और यह कह रहा हूं कि जो गुजरात में अभी सूखे की परिस्थिति है और पीने के पानी की समस्या है वह बहुत गम्भीर खड़ी हो गयी है । केन्द्र सरकार ने अभी तक जो पूरी रकम भेजनी चाहिए थी वह भी नहीं भेजी है । तत्काल यह रकम वहां भेजी जाए ताकि उससे पीने के पानी की व्यवस्था गुजरात सरकार कर सके । गुजरात सरकार के पास अभी तक पैसा नहीं गया है । केन्द्र सरकार को एक टीम भी भेजनी चाहिए । यह दो जिलों में सूखा नहीं है । पूरे सौराष्ट्र, कच्छ और जो गुजरात का वेस्टर्न पार्ट है वहां सभी जगहों पर पीने के पानी की बहुत समस्या है । इसलिए मेरी मांग है कि जल्द से जल्दी यह रकम भेजी जाए और एक टीम भी भेजी जाए ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I support the demand. This is a serious matter. The Central Government must come to the help of the Gujarat Government. The people are facing a lot of difficulties there. They are not getting water in many areas of Gujarat. I support this.

Closure of Gaya Cotton and Textile Mills, Bihar

श्री जलालुद्दीन अन्सारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण कारखाने के बारे में सवाल उठा रहा हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य में एक मात्र बिहार काटन एण्ड जूट मिल, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र में लिया गया था वह सुचारू रूप से चलाई जा रही थी । लेकिन नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को जो उस पर ध्यान देना चाहिए था वह उसने नहीं दिया और स्थिति यह हो गयी है कि अभी उसमें रुई कताई का ही काम होता है, और कपड़ा बुनाई का भी काम होता था लेकिन समय पर रुई की आपूर्ति नहीं की जाती रही है । न कोयले की आपूर्ति की जाती रही है । इसके कारण उत्पादन घटना अनिवार्य हो गया । इसके पीछे एक साजिश थी, और अभी भी चल रही है । नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की यह साजिश है कि वह गया काटन एण्ड जूट मिल को बन्द करना चाहती है । जो कपड़ा बुनाई का काम होता था पिछले साल उसको बन्द कर दिया गया है । सरकार ने जो एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है गोल्डन शेक हैंड प्रोग्राम, उसके मुताबिक ढाई-तीन सौ मजदूरों की नौकरी खत्म कर दी गयी । वह सेक्शन बंद कर दिया गया । दूसरा जो रूई कताई का सेक्शन है वह भी बंद होने की हालत में है । 28 फरवरी को मैं उस मिल में गया था । मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी जो मशीन है, वह आटोमैटिक मशीन है, नयी है लेकिन रूई न मिलने के कारण वह मशीन भी बैठी रहती है और मजदूर भी बैठे रहते हैं । दूसरी बड़ी कठिनाई है कि जो आवंटित राशि वित्तीय वर्ष में उसको मिलनी चाहिए वह भी कारपोरेशन के जरिए नहीं दी जाती है । उसके कारण उत्पादन ठप्प है । मजदूरों को कोई काम नहीं रहता है । इसके पीछे एक मात्र साजिश है कि यह दिखाया जाए कि यह मिल उत्पादन नहीं करती है । इस नाम पर वहां की जमीन को और उस मिल को बचने की साजिश चल रही है । मैं आपको बताना चाहता हूं । आपके माध्यम से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन को, कि आप मिनिस्ट्री को कहें कि वे इसको बचाए और हमारी डिमांड है आपके माध्यम से सरकार से कि इस मिल्स को रूई की नियमित आपूर्ति की जाए, जो कार्यशील राशि है उसको सही समय पर दिया जाए